भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 860
जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।
17 माघ, 1947 (शक)

आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना का कार्य-निष्पादन

860. श्री एस. सेल्वागनबेथीः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भाग लेने वाली कंपनियों की संख्या और आज की तिथि तक अनुमोदित और प्राप्त किए जा चुके कुल निवेश सहित आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत स्वीकृत आवेदनों की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) इस योजना के तहत अब तक वर्ष-वार कितना निवल वृद्धिशील उत्पादन हुआ है और पात्र वृद्धिशील बिक्री के अनुरूप कितनी प्रोत्साहन राशि संवितरित की गई है; और

(ग) क्या मंत्रालय ने विनिर्माण अक्षमता अंतराल को कम करने में इस योजना के प्रभाव का आकलन किया है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए कई नीतिगत पहलें की हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में काफी विस्तार हुआ है, जिसे निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है:

#	**2014-15**	**2024-25**	**टिप्पणियां**
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	~1.9 लाख करोड़	~11.3 लाख करोड़	6 गुना बढ़ा
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात (रु.)	~0.38 लाख करोड़	~3.3 लाख करोड़	8 गुना बढ़ा
मोबाइल फोनों का उत्पादन (रु.)	~0.18 लाख करोड़	~5.5 लाख करोड़	28 गुना बढ़ा
मोबाइल फोनों का निर्यात (रु.)	~0.01 लाख करोड़	~ 2 लाख करोड़	127 गुना बढ़ा

भारत सरकार ने देश में मोबाइल फोन के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (एलएसईएम) के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना शुरू की। मोबाइल फोन का उत्पादन वित्त वर्ष 2019-20 में 2.14 लाख करोड़ रुपये से दोगुना से अधिक बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 5.5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। परिणामस्वरूप, भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े मोबाइल निर्माता के रूप में उभरा है। मोबाइल फोन का निर्यात वित्त वर्ष 2019-20 में 0.27 लाख करोड़ रुपये से ~8 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भारत 2014 में मोबाइल फोन का आयातक होने से मोबाइल फोन का निवल निर्यातक बन गया है। दिसंबर 2025 तक, इस योजना ने 15,172 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित किया है और 1,71,448 व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसर तैयार किए हैं।
इसके बाद, भारत सरकार ने आईटी हार्डवेयर (लैपटॉप, टैबलेट, सर्वर, आदि) के लिए एक मजबूत घरेलू विनिर्माण इकोसिस्टम बनाने, बड़े निवेश को आकर्षित करने, आयात निर्भरता को कम करने और भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र बनाने के लिए 2023 में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 भी लॉन्च किया है। दिसंबर 2025 तक, योजनाओं के फलस्वरूप कुल 16,531 करोड़ रुपये का संचयी उत्पादन, 856.64 करोड़ रुपये का कुल संचयी निवेश हुआ है और कुल 4,776 (प्रत्यक्ष नौकरियां) संचयी रोजगार अवसर तैयार हुए हैं।

पीएलआई योजनाओं के तहत उत्पादन का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

विवरण	वित्त वर्ष 2023-24 (₹ करोड़)	वित्तीय वर्ष 2024-25 (₹ करोड़)	वित्त वर्ष 2025-26 (31.12.2025 तक) (₹ करोड़)
संचयी उत्पादन	4,95,660	7,66,861	10,39,218
वृद्धिशील उत्पादन	2,02,789	2,71,200	2,44,998

आयात निर्भरता को कम करने और रोजगार पैदा करने के लिए, सरकार ने पिछले 11 वर्षों में मोबाइल फोन विनिर्माण, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार आदि का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें शामिल हैं:

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017
- टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि सहित कराधान में सुधार किए गए हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के बसर्ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

******